दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि : 17.02.2023
निर्णय सुनाए जाने की तिथिः 20.03.2023

<u>आप.पु.या. 772/2018</u>

राज्य ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री नरेश चाहर, राज्य के लिए अति.लो.अभि. सह उप.नि. वीणा, थाना सराय रोहिल्ला

बनाम

सुदर्शन कुमार ...प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री योगेश स्वरूप, अधिवक्ता

<u>आप.पु.या. 565/2019 और आप.वि.आवे. 10128/2019</u>

एक्स ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री नरेश चाहर, राज्य के लिए

अति.लो.अभि. सह उप.नि. वीणा, थाना सराय रोहिल्ला

श्री संसार पाल सिंह, प्र-2 के अधिवक्ता

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

निर्णय तालिका

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि.....3

न्यायालय में प्रस्तुतियां.....5

i.न्यायिक पूर्व निर्णय.....8

ii.प्रथमदृष्टया मत.....11

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 और 90 की विधि.....12

i.न्यायिक पूर्व निर्णय.....14

विश्लेषण और निष्कर्ष.....16

i. विशेष तथ्य और परिस्थितियां.....17

ii. सम्मति का न्यायशास्त्र.....19

iii. सम्मति सहवास बनाम यौन हमला 27

iv. 12 साल का अस्पष्ट विलम्ब 28

निष्कर्ष.....30

<u>न्या.,स्वर्ण कांता शर्मा</u>

1. यह निर्णय लंबित आवेदनों के साथ-साथ आप.पु.या. 772/2018 और आप.पु.या. 565/2019 के निपटान का नियमन करेगा। चूंकि दोनों याचिकाएं समान तथ्यों और दलीलों से उत्पन्न होती हैं और दोनों याचिकाओं में इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा भी समान है, इसलिए उन पर समान निर्णय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है | आप.पु.या. 772/2018 में याचिकाकर्ता 'राज्य' है जबकि आप.पु.या. 565/2019 में याचिकाकर्ता 'अभियोक्त्री/शिकायतकर्ता' है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एतद पश्चात 'दं.प्र.सं.' के रूप में संदर्भित) की धारा 401 सपठित धारा 397 के अधीन फाइल की गई उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिकाएं भारतीय दंड संहिता, 1860 (एतद पश्चात 'भा.दं.सं.' के रूप में संदर्भित) की धारा 376/506 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दिल्ली के सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 475/2017 के मामले में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/एसएफटीसी-2 (केंद्रीय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (एतद पश्चात 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक 14.06.2018 को जारी आदेश, जिसके द्वारा अभियुक्त अर्थात आप.पु.या.772/2018 में प्रत्यर्थी एवं आप.पु.या. 565/2019 में प्रत्यर्थी सं. 2 (एतद पश्चात 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित) को भा.दं.सं. की धारा 376/506

के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से आरोपमुक्त किया गया हैं, पर अभ्याक्रमण करती हैं |

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

3. संक्षेप में, वर्तमान प्राथमिकी अभियोक्त्री की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने यह आरोप लगाया था कि उसने वर्ष 2003 में 'श्री वाई' नामक एक व्यक्ति से शादी की थी। वर्ष 2005 में ट्रेन से यात्रा के दौरान वह अभियुक्त के संपर्क में आई थी तथा दोनों में मित्रता हो गई | वह उसके घर जाने लगा था और उसके पति सहित परिवार के सदस्यों से भी मिलने लगा था। यह आरोप लगाया गया था कि नवंबर, 2005 में, अभियुक्त दयाबस्ती स्थित उस कारखाने में आया था जहां अभियोक्त्री काम करती थी। उसने उसे बाहर बुलाया और उसके बाद उसे एक गिलास जूस पिलाया, जिसके पीने के बाद वह बेहोश हो गई और अभियुक्त उसे रिक्शा में एक कमरे में ले गया। होश में आने पर, अभियोक्त्री को आभास हुआ कि अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये आरोप लगाए गए थे कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को बदनाम करने की भी धमकी दी थी। यह आरोप लगाया गया था कि लगभग 10-15 दिनों के बाद, अभियुक्त ने अभियोक्त्री को मोबाइल फोन में कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाईं और धमकाकर वह उसे पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में स्थित एक रेलवे क्वार्टर में ले गया था। उसने उसके परिवार के

सदस्यों को फोटो दिखाने की धमकी दी। इसके बाद अभियुक्त ने महिला को वर्ष 2017 तक कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जुलाई, 2017 में, अभियुक्त पालम कॉलोनी, दिल्ली में स्थित अभियोक्त्री के घर गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने उसे अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था। इसके बाद, अभियोक्त्री ने अपने पति को घटना के बारे में बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई।

4. जांच के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अभियोक्त्री का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने यह भी कहा कि उसके बेटे और बेटी का जन्म उसके और अभियुक्त के बीच शारीरिक संबंध से हुआ था। डीएनए परीक्षण किया गया और रिपोर्ट से पता चला कि बच्चों का डीएनए प्रोफाइल अभियुक्त और अभियोक्त्री के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने, दिनांक 14.06.2018 के आदेश द्वारा, अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। उक्त आदेश का प्रवर्ती हिस्सा इस प्रकार हैः

> “.....आगे यह पता चला है कि अभियोक्त्री एक विवाहित महिला है और उसके बावजूद उसने अभियुक्त के साथ संबंध बनाए। इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकती कि शादी के वादे के बहाने

अभियुक्त ने उसका दुरुपयोग किया। वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां बहुत अनूठी हैं। अभियोक्त्री वर्ष 2005 से चुप रही थी जब अभियुक्त ने कथित तौर पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अभियोक्त्री की ओर से यह बहुत असामान्य था कि वह अभियुक्त के खिलाफ शिकायत न करे या घटना के बारे में अपने पति या अपने किसी रिश्तेदार को न बताए। अभियोजन पक्ष ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच शारीरिक संबंध दिसंबर 2017 तक बने रहे, जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज अभियोक्त्री का बयान भी यहीं आशय है कि अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उसे धमकी दी थी| इस मामले में अभियोक्त्री के इस बयान की पुष्टि करने के लिए कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाए गए थे। यदि समस्त अभियोजन मामले को स्वीकार किया जाता हैं तब भी यह स्थिति बनी रहती है कि अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और विवाहित होने और पति के होने के बावजूद उससे दो बच्चों को जन्म दिया, जो यह दर्शाता है कि उसने अभियुक्त के साथ अपनी इच्छा से संबंध स्थापित किए हैं |अभियुक्त के जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न भी सर्वोपरि है। किसी अभियुक्त को उस मामले में विचारण का सामना करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है जहां मामले का परिणाम स्पष्ट है और इस प्रकार वह अभियुक्त के पक्ष में जाएगा। इन परिस्थितियों में,

अभियोक्त्री को यदि न्यायालय में उसके बयान के आधार पर बुलाया जाए तब भी वह पुलिस को दिए गए तथा विद्वान महानगरीय दंडाधिकारी के समक्ष दिए गए अपने बयान के अतिरिक्त कुछ और बयान नहीं दे सकती है। इन परिस्थितियों में, मैं राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. के दलीलों में कोई गुणागुण नहीं पाता। अभियुक्त के विरूद्ध शायद ही कोई सामग्री है जो यह दिखाए कि उसने अभियोक्त्री को उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए धमकी दी है| तदनुसार, अभियुक्त सुदर्शन को भा.दं.सं. की धारा 376/506 से दोषमुक्त किया जाता है..."

<u>न्यायालय में प्रस्तुतियां</u>

6. अभियोक्त्री/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा हैं कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर गंभीर त्रुटी की। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि यह सच है कि इस मामले में अभियोक्त्री द्वारा आरोप कथित घटना, जब पहली बार अभियुक्त द्वारा उस पर यौन हमला किया गया, के 12 साल बाद लगाया गया लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय को दं.प्र.सं. की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए अभियोक्त्री के बयानों से परे नहीं जाना चाहिए था| विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि इस तथ्य के बावजूद की अभियोक्त्री के अभियुक्त से दो बच्चें, यह आरोप के विरचना में बाधा नहीं पहुचाएगा, चूँकि

न्यायालय को आरोप के विरचना के समय केवल अभियोक्त्री द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 161 एवं 164 के अंतर्गत दिए गए बयानों पर विचार करना है उससे परे नहीं |

7. राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. यह भी तर्क देते है कि अभियोक्त्री द्वारा उसके शिकायत और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान में लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने चाहिए थे और आरोपों की सत्यता का परीक्षण विचारण के स्तर पर किया जा सकता है।

8. दूसरी ओर, अभियुक्त के विद्वान वकील ने कहा कि अभियोक्त्री ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत अपने बयानों में स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से दो बच्चों को जन्म दिया था जो दर्शाता है कि वह उसके साथ सम्मति से संबंध में थी। यह पुरजोर तर्क दिया गया है कि अभियोक्त्री वर्ष 2005 से चुप रही, जब कथित रूप से अभियुक्त ने उसकी सम्मति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और वर्ष 2017 में आकर शिकायत की, अतएव उसके झूठे एवं तुच्छ आरोप लगाए। यह प्रस्तुत किया जाता हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या दोष नहीं है |

9. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

10. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा जिस मुद्दे का निर्णय किया जाना है, वह यह है कि क्या प्राथमिकी और आरोप-पत्र में यथानुसार सभी अभिकथनों पर विचार करते हुए, भा.दं.सं. की धारा 376/506 के अधीन दंडनीय अपराध आरोप विरचित करने के प्रयोजन बनते हैं या नहीं।

<u>आरोप विरचना पर विधि</u>

11. पक्षकारों की प्रतिद्वंदी दलीलों और मामले के गुणावगुण पर विचार करने के पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और 228 के अधीन यथा उपबंधित आरोप की विरचना और उन्मोचन के संबंध में विधि पर संक्षेप में चर्चा करना उचित होगा। यह सन्दर्भ हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैं:

> "227. **उन्मोचन**
>
> यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा |

228. **आरोप की विरचना**

(1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार, और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसे अपराध किया है जो-

(क) अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर एकता है और आदेश द्वारा, मामले की विचरण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसी तारीख को जो ठीक समझे, अभियुक्त को, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निदेश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलो के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा ;

(ख) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध लिखित रूप से विरचित करेगा |

(2) जहाँ न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहां वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पुछा जायेगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है |

i. न्यायिक पूर्व निर्णय

12. ***भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल*** *(1979) 3 एस. सी. सी. 4*, वाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरोप की विरचना/उन्मोचन के चरण में विचार करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए थेः

> " 10. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों के विचारण द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते है :
>
> 1. संहिता की धारा 227 के अधीन आरोप विरचित करने के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायाधीश को यह पता लगाने के सीमित प्रयोजन के लिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता हैं **या नहीं, प्राथमिक साक्ष्य की छानबीन एवं आंकलन की स्पष्ट शक्ति प्राप्त है** ।
>
> 2. जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह प्रकट करती है, जिसे उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां न्यायालय आरोप विरचित करने और विचारण के साथ कार्यवाही करने में पूरी तरह न्यायोचित होगा।
>
> 3. प्रथमदृष्टया मामले का अवधारण करने का **परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा** और एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम बनाना कठिन है। **सामान्यतः, यदि दो मत समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश को यह संतुष्टि हो जाती है कि उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कुछ संदेह तो पैदा होता है किंतु**

यह संदेह गंभीर नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करने के अपने अधिकार के अंतर्गत होगा।

4. संहिता की धारा 227 के अधीन अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायाधीश, जो वर्तमान संहिता के अधीन **वरिष्ठ और अनुभवी न्यायालय हैं केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें मामले की व्यापक संभाव्यताओं, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों के कुल प्रभाव, में दिखाई देने वाली किसी भी आधारभूत कमियों पर विचार करना होगा।** मामला इत्यादि। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और विपक्ष की जांच करनी चाहिए और साक्ष्य को इस प्रकार तौलना चाहिए मानो वह विचारण कर रहा हो।

(जोर दिया गया)

13. सज्जन कुमार बनाम सीबीआई (2010) 9 एस. सी. सी. 368 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने आरोप की विरचना और उन्मोचन के संबंध में न्यायालयों की शक्तियों पर विचार किया है कि प्रथमदृष्टया मामला प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।उक्त निर्णय में प्रतिपादित प्रासंगिक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

"21. संहिता की धारा 227 और 228 की व्याप्ति के बारे में प्राधिकारियों के विचार पर निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

(i) न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 227 के अधीन आरोप विरचित करने के प्रश्न पर विचार करते समय इसमें संदेह नहीं किया है। **यह पता लगाने के सीमित प्रयोजन के लिए कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं, साक्ष्य को छानने और तौलने की शक्ति प्रथमदृष्टया मामलों को निर्धारित करने का परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।**

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह प्रकट करती है जिसे उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां न्यायालय आरोप विरचित करने और विचारण के साथ कार्यवाही करने में पूरी तरह न्यायोचित होगा।

(iii) न्यायालय केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता बल्कि उसे मामले की व्यापक संभाव्यताओं, साक्ष्य के कुल प्रभाव और न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों, किसी भी आधारभूत दुर्बलता आदि पर विचार करना होता है।

(iv) यदि अभिलिखित पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय यह राय बना सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो वह आरोप विरचित कर सकता है, यद्यपि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना अपेक्षित है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

(v) आरोप की विरचना के समय अभिलेख के पहले सामग्री के प्रोबेटिव मूल्य के पहले विचार नहीं किया जा सकता किंतु आरोप की विरचना से पूर्व न्यायालय को अभिलेख के पहले रखी गई सामग्री के पहले अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए और इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अके पहले ाध किया जाना संभव था।

(vi) **धारा 227 और 228 के प्रक्रम पर, न्यायालय को यह पता लगाने की दृष्टि से अभिलेख सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उनमें से उभरते हुए तथ्य अभिकथित अपराध गठित करने वाले सभी अवयवों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्य की छानबीन करना , क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष उन सभी बातों को प्रतिग्रहण कर लेगा, जो सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हैं।**

(vii) **यदि दो मत संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जो कि गंभीर संदेह से अलग है, तो विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए सशक्त किया जाएगा और इस स्तर पर, उसे यह नहीं देखना है कि क्या विचारण दोष-सिद्धि या दोष-मुक्ति में समाप्त होगा।"**

(जोर दिया गया)

ii. प्रथमदृष्टया व्यू

14. आरोप की विरचना के संबंध में राय बनाने का आधार यह है कि क्या प्रथमदृष्टया अपराध के किए जाने का मामला बनाने के लिए अभिलेख सामग्री पर्याप्त है। इसलिए, विचारण न्यायालय के न्यायधीशों को यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे इस तरह की राय बनाने के लिए उनके समक्ष रखी गई सामग्री पर सावधानीपूर्वक अपना दिमाग लगाएं.

15. इमारत मामले के प्रथमदृष्टया दृष्टिकोण का मूल्यांकन है। अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रासंगिक प्रश्न पर विचार किया जाए कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर प्रथम-दृष्टया विचार क्या गठित करता है।

16. प्रथमदृष्टया किसी ऐसी चीज को निर्दिष्ट करता है जिसे पहली नजर में, पहले प्रभाव में, धरातल पर, या प्रारंभिक प्रकटीकरण से साबित या, निर्धारित किया जा सकता है। ब्लैक की विधिक शब्दावली, 5वां संस्करण सुझाव देता है कि प्रथमदृष्टया मामले का अर्थ यह होगा कि अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य उस निष्कर्ष की यथोचित अनुमति देगा जो अभियोक्ता चाहता है। अतः, 'प्रथम दृष्टया' से ऐसा सुझाव अभिप्रेत है जो किसी भी बात पर पहली नजर डालने से आता है।

17. मॉडर्न ग्रीक की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, 'प्रथमदृष्टया' का शाब्दिक अर्थ 'पहले देखना' है। इसका मतलब ज़रूर होगा कि किसी चीज को

उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर देखना और किसी जटिल या विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाना, इसलिए जहां तक आरोप पर विचार करने का संबंध है, प्रथमदृष्टया शब्द का उपयोग करने का मतलब होगा की पर्याप्त सामग्री जो अभियुक्त के खिलाफ मजबूत संदेह और अभियोजक के पक्ष में विचार प्रस्तुत करेगा।

<u>भारतीय दंड संहिता संहिता, 1860 की धारा 375 और 90 का कानून</u>

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आने वाला अपराध दंडनीय है यदि बलात्कार का अपराध धारा 375 के निबंधनों के अनुसार साबित होता है जो अपराध के अवयवों को वर्णित करता है। वर्तमान मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के साथ धारा 375 भी प्रासंगिक है जो नीचे वर्णित हैः

> "**375. बलात्कार** - यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित सात वर्णनों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों मकरता है तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति गंभीर बलात्कार करता है।
>
> (क) किसी स्त्री की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक उसके लिंग को प्रवेश कराता है या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए बाध्य करता है. या

(ख) किसी वस्तु या निकाय, शरीर के किसी भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी सीमा तक अंतर्वेशित करता है या उससे ऐसा कराता है. या

(ग) किसी महिला के निकाय, शरीर के किसी भाग में हेरफेर करता है जिससे कि ऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या निकाय, शरीर के किसी भाग में प्रवेश हो सके या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सके; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या निम्नलिखित सात वर्णनों के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए उसे बाध्य करता हैः-

सबसे पहले- उसकी इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा- उसकी सम्मति के बिना।

तीसरी बात- उसकी सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह रुचि रखती है, मृत्यु या चोट के डर से रखकर प्राप्त की गई हो।

चौथा - उसकी सम्मति से, जब पुरुष को पता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सम्मति इसलिए दी जाती है क्योंकि वह विश्वास करती है कि वह एक अन्य पुरुष है जिससे वह कानूनी रूप से विवाहित है या विश्वास करती है।

पांचवां - अपनी सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देते समय, मन की अस्वस्थता या नशे या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी भी अस्थिर या हानिकारक पदार्थ द्वारा या स्वयं के प्रशासन द्वारा, या मादक पदार्थ, या अस्वास्थकर पदार्थ, वह उस प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ होती है जिसे वह सम्मति देती है।

छठा - उसकी सम्मति के साथ या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की हो।

सातवीं - बात-जब वह सम्मति व्यक्त करने में असमर्थ होती है।

व्याख्या 1. - इस खंड के उद्देश्यों के लिए योनि में लैबिया मेजोरा भी शामिल होगा।

व्याख्या 2. - सम्मति का अर्थ है एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता जब महिला शब्दों, हाव-भाव या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार के माध्यम से विशिष्ट यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती हैः

बशर्ते कि कोई महिला जो शारीरिक रूप से प्रवेश के कार्य का विरोध नहीं करती है, उसे केवल इस तथ्य के कारण यौन गतिविधि के लिए सम्मति देने वाली नहीं माना जाएगा।

अपवाद 1. - चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा।

अपवाद 2 - किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ, जिसकी आयु पंद्रह वर्ष से कम नहीं है, यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है।

"90. भय या गलत धारणा के तहत दी जाने वाली सम्मति - सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसा कि इस संहिता के किसी भी खंड द्वारा अभिप्रेत है, यदि सम्मति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के डर से या वास्तव में गलत धारणा के तहत दी जाती है, और अगर कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, कि सम्मति ऐसे डर के परिणामस्वरूप दी गई थी या..."।

i. न्यायिक पूर्व निर्णय

19. ***डॉ. धुवरम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य*** *(2019) 18 एससीसी 191* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त प्रावधानों की योजना पर निम्नलिखित रूप में चर्चा की थी:

"15. धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है और अपराध के छह विवरणों की गणना करती है। पहला खंड वहां लागू होता है जहां महिलाएं अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखती हैं और इसलिए, सम्मति देने में सक्षम हैं, लेकिन यह कार्य उनकी इच्छा के खिलाफ किया जाता है और दूसरा खंड जहां यह उनकी सम्मति के बिना किया जाता है; तीसरा,चौथा और पांचवां जब सम्मति होती है, लेकिन यह माफी के रूप में

ऐसी सम्मति नहीं है, क्योंकि यह उसे या किसी व्यक्ति को, जिसमें वह रुचि रखती है, मृत्यु या चोट के डर से प्राप्त किया जाता है। "सम्मति के बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि मामला केवल साक्ष्य या संभाव्यताओं के आधार पर है।" "आम सम्मति" को विचार-विमर्श के साथ-साथ एक तर्कसंगत कार्य भी कहा गया है।"यह शिकायत किए गए कार्य को करने की अनुमति देने के लिए एक व्यक्ति की सक्रिय इच्छा को दर्शाता है।

16. भारतीय संहिता की धारा 90 भय या गलत धारणा के तहत दी जाने वाली सम्मति को परिभाषित करती हैः-

“धारा 90: सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसा कि इस संहिता के किसी भी खंड द्वारा अभिप्रेत है, यदि सम्मति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के डर से या वास्तव में गलत धारणा के तहत दी जाती है, और अगर कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, कि ऐसे डर के परिणामस्वरूप दी गई थी।

17. इस प्रकार, धारा 90 यद्यपि “सम्मति” को परिभाषित नहीं करती है किंतु “सम्मति” क्या है उसका वर्णन करती है। सम्मति व्यक्त की जा सकती है या व्यक्त की हो सकती है, मजबूर किया जा सकता है या गुमराह किया जा सकता है, स्वेच्छा से या छल द्वारा से प्राप्त किया जा सकता है। यदि शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों की गलत धारणा के तहत सम्मति दी जाती है, तो यह विकृत हो जाती है। धारा 375 के उद्देश्य के लिए सम्मति

के लिए स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता है, न केवल अधिनियम के महत्व और नैतिक गुणवत्ता के ज्ञान पर आधारित बुद्धिमत्ता के अभ्यास के बाद, बल्कि प्रतिरोध और अनुमति के बीच चयन का पूरी तरह से उपयोग करने के बाद भी। कोई सम्मति थी या नहीं, यह सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद ही पता लगाया जा सकता है।"

20. ***कैनी राजन बनाम केरल राज्य*** *(2013) 9 एससीसी 113* के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के अपराध की अनिवार्यताओं और मापदंडों की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया थाः

"12. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 "बलात्कार" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, जो इंगित करती है कि पहला खंड संचालित होता है, जहां महिला अपनी इंद्रियों के वश में है, और इसलिए, सम्मति देने में सक्षम है, लेकिन कार्य उसकी इच्छा के खिलाफ किया जाता है और दूसरा,जहां यह उसकी सम्मति के बिना किया जाता है-तीसरा, चौथा और पांचवां-सम्मति होती है, लेकिन यह ऐसी सम्मति नहीं है जो अपराधी को बहाना बनाती है, क्योंकि यह उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर डालकर प्राप्त किया जाता है जिसमें वह मृत्यु या चोट के डर से इच्छुक है।" ""सम्मति के बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि केवल मामले के साक्ष्य या संभाव्यताओं के आधार पर। "आम सम्मति" "को विचार-विमर्श के साथ-साथ एक तर्कसंगत कार्य भी कहा गया है।" ""यह एक व्यक्ति के मन में शिकायत किए गए

> कार्य को करने की अनुमति देने की सक्रिय इच्छा को दर्शाता है।"" "भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 90 में "सम्मति के लिए सम्मति" "अभिव्यक्ति का निर्देश किया गया है।"तथापि, खंड 90 में सम्मति को परिभाषित नहीं किया गया है किंतु यह वर्णित किया गया है कि सम्मति क्या है। खंड 375 के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता न केवल महत्व के ज्ञान के आधार पर बुद्धिमत्ता के प्रयोग के बाद है, और अधिनियम की नैतिक गुणवत्ता, लेकिन प्रतिरोध और अनुमति के बीच चयन का पूरी तरह से उपयोग करने के बाद। सम्मति थी या नहीं, इसका पता सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद ही लगाया जा सकता है।"

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

21. वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, याचिकाकर्ताओं की दलीलें मुख्य रूप से इस आधार पर हैं कि वर्ष 2005 में अभियोक्त्री को एक सार्वजनिक स्थान पर अर्थात उसके कार्य स्थल के पास एक जूस की दुकान पर किसी प्रकार का मादक पदार्थ दिया गया था और बाद में, उसने खुद को अभियुक्त के घर में पाया था जो एक सरकारी क्वार्टर था और उसे होश में आने पर एहसास हुआ था कि उसके साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया था। बाद में, अभियुक्त ने उसे यह भी बताया कि उसने उसकी एक वीडियो क्लिप बनाई थी और कई अनुचित तस्वीरें ली थीं, और उसके बाद उसने इस तरह की

धमकियों के आधार पर कई वर्षों तक अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वर्ष 2005 से लेकर, वर्ष 2017 में शिकायत दर्ज होने तक, अभियोक्त्री ने न तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को इसकी सूचना दी।

22. इस प्रकार, इस न्यायालय को स्थापित विधि और पूर्व निर्णय के आलोक में यह विनिश्चय करना है कि क्या मामले के तथ्य अभियुक्त के विरुद्ध 'प्रथम दृष्टया' बलात्कार का मामला बनाते हैं या नहीं।

23. अभियोक्त्री के बयान और अभिलेखित अन्य सामग्री के अवलोकन से असामान्य तथ्य सामने आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं, जिन पर यह न्यायालय अब चर्चा करने और आगे के पैराग्राफों में विचार करने के लिए आगे बढ़ता है.

i. विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियां

24. वर्तमान मामले में विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियां शामिल हैं। वर्ष 2005 में पहली कथित घटना दिन के उजाले में हुई थी जब एक जूस की दुकान पर अभियोक्त्री को कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिया गया था।इसके तुरंत बाद बलात्कार की घटना कथित रूप से एक भीड़भाड़ वाले, अत्यधिक आबादी वाले

सरकारी क्वार्टरों में होती है, जहां एक ही रास्ता और एक ही प्रवेश द्वार होता है।

25. अनिवार्य रूप से 12 वर्षों के बाद, जूस की दुकान का मालिक पुलिस द्वारा नहीं पाया गया होगा और उसके बाद न तो दुकान से कोई संकेत मिला होगा, न ही दुकान का कोई सटीक स्थान या जगह या कोई व्यक्ति जो अपहरण को देखने के लिए सर्वोत्तम गवाह रहा होगा। अभियोक्त्री खुद कहती है कि नवंबर, 2005 में, उसे मुख्य सड़क पर जूस का गिलास दिया गया था और उसे दिन के उजाले में रिक्शा में बैठाया गया था, जहां वह रिक्शा में बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया था, तो उसे एहसास हुआ था कि अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। प्रथमदृष्टया, इस बयान से यह संकेत मिलता है कि उनके दावों पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि मुख्य सड़क पर दिन के समय, वह भी दिल्ली के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक पर, उन्हें जूस की दुकान पर जूस के गिलास में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था और उसके बाद उन्हें एक रिक्शा में ले जाया गया, जहां वह बेहोश हो गईं। कोई व्यक्ति दिन के उजाले में रिक्शा में बेहोशी की हालत में एक पूरी तरह से वयस्क महिला को दिल्ली के दूसरे व्यस्त स्थान यानी रेलवे क्वार्टर, दया बस्ती ले जा रहा है, बल्कि उसकी कहानी के खिलाफ सवाल उठाता है।

26. इसके बाद, अभियोक्त्री को कथित तौर पर अभियोक्ता द्वारा अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की गई अनुचित तस्वीरें और वीडियो,दिखाया गया। जिन्हें जांच एजेंसियों द्वारा कभी भी बरामद नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि जिस मोबाइल नंबर या मोबाइल फोन में कथित वीडियो और फोटोग्राफ को अभियोक्त्री को दिखाया गया था, वह न तो आरोप-पत्र का हिस्सा है और न ही बरामद किया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसे क्यों ठीक नहीं किया गया था। अभियोक्त्री ने खुद अपने बयान में कहा कि उसे एक सफेद अंडाकार मोबाइल फोन में तस्वीरें और वीडियो दिखाए गए थे, जो उसने वर्ष 2005 में नहीं देखे थे और न ही उसने मोबाइल फोन दिखाए जाने के दिन से के पहले इसे देखा था,न ही उसने उसके बाद अभियुक्त के पास फोन देखा था। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह की तस्वीरों या वीडियो के डर से अभियोक्त्री की सम्मति कैसे प्राप्त की गई।

27. शिकायतकर्ता के साथ-साथ अभियुक्त ने, अभिकथित पहली घटना के समय से अंतिम घटना तक, विभिन्न भागीदारों से विवाह कर लिया था। दोनों 2005 से यौन संबंध बनाए हुए हैं, जो अभियुक्त के घर पर अक्सर होता था, जहां अभियुक्त द्वारा उसे नियमित आधार पर विभिन्न तरीकों से ले जाया जाता था, जहां यौन गतिविधि कथित रूप से उसकी सम्मति के खिलाफ हुई थी। इससे भी अधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब दोनों अपने जीवित

और कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के साथ रह रहे थे, तब वे न केवल रिश्ते में थे, जिसे अब शिकायतकर्ता अपनी इच्छा के खिलाफ होने का आरोप लगाती है, बल्कि यह इस कारण से भी झूठा या संदिग्ध प्रतीत होता है कि उसने दो बच्चों को जन्म दिया है, जिनका पिता अभियुक्त है। तथ्य स्पस्ट नहीं करते हैं कि अभियोक्त्री के परिवार को डीएनए परीक्षण तक बच्चों के पालन-पोषण के बारे में भी कैसे पता नहीं था। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसने परिवार या किसी अन्य प्राधिकारी को सूचित क्यों नहीं किया कि उसकी सम्मति के बिना 12 वर्षों से उसका यौन शोषण किया जा रहा था, या उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था और उसने यहां अभियुक्त द्वारा पैदा किए गए बच्चों को भी जन्म देने का विकल्प चुना। यह कोई किशोरी, अशिक्षित महिला या 12 साल से यौन हमले के बाद बंधक व्यक्ति का मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां हर यौन मुठभेड़ के लिए,वह अभियुक्त के घर गई थी और उसके बाद घर वापस चली गई थी और इस तरह के यौन संयोजन से दो बच्चों को जन्म दिया था।

ii. सम्मति का न्यायशास्त्र

28. इस देश का कानून महिलाओं के मूल अधिकारों सहित यौन स्वायत्तता, यौन आत्मनिर्णय और समानता के महिला के अधिकार की पुष्टि करते हैं जो व्यक्तिगत मानवाधिकार हैं। कई वर्षों तक, यौन उत्पीड़न को हिंसा के उपयोग

के साथ यौन गतिविधियों के साथ पहचाना जाता था और उसकी अनुपस्थिति को प्रश्नगत यौन गतिविधि के लिए उसकी सम्मति माना जाता था। हालांकि, भारत और कई अन्य देशों में यौन उत्पीड़न और यौन सम्मति न्यायशास्त्र के विकास के साथ, शारीरिक अखंडता का अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है और हिंसा की अनुपस्थिति में सभी मामलों में बलात्कार के सभी मामलों का संकेत नहीं है। हाल के वर्षों में भारत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न कानूनों में व्यापक सुधार और इस संबंध में न्यायशास्त्र का विकास देखा गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीड़ित की इच्छा के खिलाफ यौन गतिविधि यौन हमले का मुख्य और आवश्यक घटक है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि पीड़ित की यौन स्वायत्तता का उल्लंघन एक अपराध है।

29. अभियोक्त्री के विद्वान अधिवक्ता चाहते हैं कि यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करे कि अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच पहला यौन मुठभेड़ उसकी सम्मति के विरुद्ध था और यदि यह माना जाता है कि 12 वर्षों की मध्यवर्ती अवधि के लिए, दो वयस्क व्यक्तियों के बीच सम्मति से संबंध थे, तो अंतिम यौन मुठभेड़ उसकी इच्छा के विरुद्ध थी और इसलिए, उसकी ईच्छा के विरुद्ध इन दो यौन मुठभेड़ों के आधार पर मुकदमा शुरू किया जाना है।

30. हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क इस न्यायालय में कोई पक्षपात नहीं करता है। वर्तमान मामले में, न तो अभियोक्त्री का कोई मोबाइल फोन, या तस्वीरें, या वीडियो है, न ही इस बात का कोई सबूत है कि यह कभी भी अभियुक्त के पास था। इसके अलावा, अंतिम घटना कथित रूप से अभियोक्त्री के अपने घर में हुई है। अभियोक्त्री और अभियुक्त का 12 वर्षों का यौन संबंध रहा है और यौन संबंध से दो बच्चों का जन्म हुआ है, इसलिए, यह आरोप लगाना या यह मानना कि उनका अंतिम संबंध सम्मति के बिना था और इसे बलात्कार कहना इस संबंध में न्यायिक पूर्व निर्णयों के खिलाफ होगा। जैसा कि पहले देखा गया है, इस मामले में बलात्कार विवाह के किसी झूठे झांसे पर नहीं हुआ है, बल्कि केवल कुछ तस्वीरों और एक वीडियो के आधार पर हुआ है, जो कथित रूप से अभियुक्त के कब्जे में था, जिस पर भरोसा नहीं किया गया है या अभियोजन द्वारा बरामद नहीं किया गया है। अभियोक्त्री का किसी को भी मामले की जानकारी न देने का आचरण, और उनके संयोजन से दो बच्चे पैदा करने वाले अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों, और इस बीच उनके अपने जीवनसाथी के साथ रहने का उनका आचरण जब व्यभिचार अभी भी एक आपराधिक अपराध था, तो कुछ हद तक उनके अपने आचरण के बारे में सवाल उठाता है।

31. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय केवल यह निर्णय करने के लिए अभियोक्त्री के बयानों पर निर्भर करता है कि क्या, प्रथमदृष्टया में, अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन मामला बनता है या नहीं।

32. इस संबंध में, निम्नलिखित के विनिश्चय के प्रति निर्देश किया जा सकता है **सोनू @ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश *2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 181***,** जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं ***प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य*** *(2019) 9 एससीसी 608*:

> "10. इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया हैः
>
> "उपर्युक्त मामलों से उभर कर सामने आने वाली विधिक स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, धारा 375 के संबंध में किसी महिला की सम्मति प्रस्तावित अधिनियम की दिशा में एक सक्रिय और तर्कसंगत विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए। यह सिद्ध करने के लिए कि क्या विवाह करने के वादे से उत्पन्न होने वाले तथ्य की गलत धारणा के कारण सम्मति अमान्य थी, दो प्रस्तावों को जरूर स्थापित किया जाना चाहिए।विवाह का वादा निश्चित रूप से एक झूठा वादा था, जो असद्धाव ; दुर्भाव के साथ किया गया था और जिस समय यह किया गया था उस

समय इसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था। झूठे वायदे की तत्काल प्रासंगिकता होनी चाहिए, या यौन कार्य में संलग्न होने के महिला के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए।"

33. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य*** *2013 7 एससीसी 675* में अभिनिर्धारित किया गया है, सम्मति स्वेच्छा से या छल द्वारा से अभिव्यक्त या विवक्षित, मजबूर या गुमराह, प्राप्त की जा सकती है। सम्मति तर्क का एक कार्य है, जिसके साथ विचार-विमर्श, दिमाग को तौलना, जैसे बाकी; अतिशेष; संतुलन में, दोनों तरफ अच्छाई और बुराई है।"

34. इस प्रकार, विभिन्न पूर्व निर्णय से यह विधिक स्थिति उभर कर सामने आई है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के संबंध में किसी महिला की सम्मति यौन संभोग की दिशा में सक्रिय और तर्कसंगत विवेचना होनी चाहिए।

35. वर्तमान मामले में, यह स्थापित करने के लिए कि क्या सम्मति मानहानि के डर से प्राप्त की गई थी, जो मुख्य रूप से अभियुक्त के कब्जे में कथित फोटोग्राफ और वीडियो होने के कारण उत्पन्न हुई थी, यह न्यायालय निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देता हैः

i. अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच **12 वर्षों के लंबे** समय तक **निरंतर यौन संबंध** थे, जबकि दोनों की शादी अलग-अलग जीवनसाथियों से हुई थी।

ii. **पक्षकारों के बीच संबंध उनके संबंधित विवाहों के निर्वाह के दौरान जारी रहे।** दोनों पक्षकार वयस्क और श्रमजीवी/कार्यरत थे। अभियोक्त्री एक कारखाने में काम कर रही थी और अभियुक्त एक सरकारी सेवा में कार्यरत था।

iii. **अभिलेख से किसी भी अनुचित फोटो, वीडियो या धमकी के होने का कोई सबूत नहीं है** या कोई भी मोबाइल फोन जिसमें ऐसी तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती थी।

iv. दिन के उजाले में **नशीले पदार्थों के सेवन के किसी भी आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।** एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में, 12 साल बीत जाने के बाद।

v. **यह अभियोक्त्री का मामला नहीं है कि उसके पास अधिकारियों** या यहां तक कि अपने परिवार को भी अभियुकत द्वारा कथित यौन शोषण बारे में सूचित करने की क्षमता की कमी थी।

vi. **अभियुक्त द्वारा पिता बनाए गए बच्चों को जन्म देने के लिए अभियोक्त्री की खुद की पसंद और सम्मति**, किसी को भी शिकायत की फुसफुसाहट

vii. अभियोक्त्री को सीमित नहीं किया गया था और वह अपने पति सहित अपने परिवार के साथ रहने, किसी भी स्थान पर जाने, अपने काम पर जाने और यहां तक कि बिना किसी धमकी या डर के बच्चों को जन्म देने के उद्देश्य से डॉक्टर के पास जाने के लिए स्वतंत्र थी।

36. उपर्युक्त परिस्थितियों में, यह मानना यौन सम्मति के न्यायशास्त्र के खिलाफ होगा कि केवल एक ही वाक्य के आधार पर, एक ही पक्ष के बीच 12 लंबे वर्षों के लिए सम्मति की अनदेखी करते हुए और तथ्यों, परिस्थितियों और प्रश्नगत पक्षकारों के आचरण पर भी विचार करते हुए आरोप विरचित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने यह भी मत भी व्तक्त किया कि ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं जो विवादित हैं और जैसा कि रिकॉर्ड में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375/506 के तहत अपराधों के अवयव स्थापित नहीं किए गए हैं.

37. वर्तमान मामले में मुख्य रूप से विवाद की जड़ यह है कि क्या यौन संबंध के लिए अभियोक्त्री की सम्मति भय के तहत थी और इसलिए, कानून

की नजर में कोई सम्मति नहीं थी या क्या यह एक सचेत सम्मति थी। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यहां तक कि प्रथमदृष्टया भी, अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोपों का अर्थ लगाना मुश्किल है कि उन्हें 'बलात्कार' की परिभाषा के तहत कवर किया जाना चाहिए-अभियोक्त्री एक अन्य साथी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते, उसके पास उन कार्यों के महत्व, परिणाम और महत्व को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्वता और बुद्धिमत्ता थी जो वह कर रही थी और जिसके लिए वह सहमत थी जिसमें नैतिक पहलू भी शामिल हैं।तथ्यों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि एक तरफ, उसने अपने पति के साथ कानूनी रूप से विवाहित दूसरे व्यक्ति से दो बच्चों को जन्म देकर विवाह की आस्था और पवित्रता के साथ विश्वासघात किया था, वहीं दूसरी ओर, अभियुक्त खुद भी अपने कानूनी रूप से विवाहित साथी के साथ विश्वासघात कर रहा था। यहां तक कि जब वह दो बार गर्भवती थी, तब भी उसने अपने पति को यह नहीं बताया कि वह अभियुक्त से गर्भवती थी और वह उसके बच्चों को जन्म देने के लिए आगे बढ़ गई थी, जो उसके लिए आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि वह अभी भी अपने कानूनी रूप से विवाहित पति के साथ रह रही थी, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा है कि वह जानती थी कि दोनों बच्चे अभियुक्त द्वारा पिता बनाए गए थे, इसलिए, वह

स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह अभियुक्त से गर्भधारण कर रही थी, न कि उसके कानूनी रूप से विवाहित पति से।

38. अभिलेख पर सामग्री यह भी इंगित नहीं करती है कि सम्मति बल के उपयोग पर आधारित थी और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने स्वयं पुलिस को बयान दिया है कि कथित सफेद रंग का अंडाकार मोबाइल फोन एक बार उसे पल भर के लिए दिखाया गया था और उसने इसे फिर कभी नहीं देखा था, पक्षकारों के बीच एक समझौते की ओर इशारा करती है। इस प्रकार, यह इंगित करता है कि उसके परिवार को दिखाई जा रही तस्वीरों और वीडियो की कोई निरंतर धमकी नहीं थी, क्योंकि मोबाइल फोन खुद कभी बरामद नहीं किया गया था क्योंकि फोन का विवरण और विवरण कभी भी अभियोक्त्री द्वारा नहीं दिया गया था.इस फोन का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध नहीं है।

39. यह तथ्य कि इस मामले में शिकायतकर्ता स्वयं पुलिस के पास गई थी और उसने यह आरोप लगाते हुए दो बच्चों के डीएनए परीक्षण के लिए अनुरोध किया था कि उन्हें उसके द्वारा जन्म दिया गया था, इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि यद्यपि वह अपने पति के साथ एक वैवाहिक संबंध में रह रही थी, वह जानती थी कि बच्चों का पिता इसी व्यक्ति ने बनाया है। इसलिए, यह उनके इस तर्क का खंडन करता है कि 12 वर्षों से उनके साथ

किया गया प्रत्येक कार्य बिना सम्मति के था। इसलिए बच्चे स्वयं शिकायतकर्ता की सम्मति से पैदा हुए थे।

40. यह न्यायालय यह भी नोट करता है कि यह 12 वर्ष की लंबी अवधि का गैर-अजनबी यौन संबंध का मामला है। चूंकि यौन सम्मति के सबूत यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि क्या यौन उत्पीड़न का अपराध मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों में हुआ था, इसलिए वर्तमान मामले के तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मामले के तथ्यों में, सम्मति के संचार में या तो शब्द या आचरण शामिल हो सकते हैं जो स्पष्ट होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 375 का स्पष्टीकरण भी इसी ओर इंगित करता है।इसलिए, आवश्यक रूप से, सम्मति का संचार संबंधित व्यक्ति के तथ्यों और आचरण से एकत्र किया जाना चाहिए।इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कानून को उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो ब्लैकमेलिंग या धमकियों के आधार पर यौन शोषण/हमले के प्रति प्रथमदृष्टया संवेदनशील हो सकते हैं। हालांकि, इस तरह की सुरक्षा उस सामाजिक संदर्भ में उपलब्ध नहीं हो सकती है, जिसमें परिचित या दोस्त 12 साल तक यौन संबंध में रहे हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में इस तरह के यौन संबंध से पैदा हुए दो बच्चों के साथ है।

41. इस प्रकार, वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अभियोजक की सहमति निहित थी और साथ ही व्यक्त की गई थी जिसे छल के माध्यम से मजबूर या गुमराह या प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि अभियोजक 12 वर्षों से उसके साथ यौन संबंध रखता है। जब वह अपने कानूनी रूप से विवाहित पति के साथ लगातार रहते हुए आरोपी द्वारा दो बच्चों को जन्म दिया, उसकी सहमति तर्क पर आधारित, विचार-विमर्श के बाद और दोनों पक्षों के अच्छे और बुरे को तौलने पर आधारित होनी चाहिए।

42. किसी न्यायालय को, ऐसी परिस्थितियों में, **अभियुक्त के पारस्परिक संबंधों** की गतिशीलता और क्या शिकायतकर्ता पर किसी धमकी के कारण इनकार करने के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया था। तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि दोनों पक्षों ने यौन आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग किया था और अपने स्वयं के वैध विवाहित पति/पत्नी के साथ रहते हुए शारीरिक संबंध बनाए रखे थे और दो बच्चों को जन्म दिया था जबकि यौन संबंध दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में सरकार द्वारा प्रदत्त अभियुक्त के घर में हुआ था।

43. यह ऐसा मामला नहीं है जहां अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की किसी भी दुर्बलता या शक्ति की कमी का शोषण या दुरुपयोग किया हो या चोट के किसी भी डर के तहत उसे रखा हो जिसके कारण वह 12 साल तक संबंध में

रही हो और 12 साल के बाद उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी हो और खुद की स्वेच्छा से खुलासा किया हो कि दोनों बच्चे अभियुक्त द्वारा पैदा किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि यह तथ्य उसके अपने परिवार और उसके पति को भी पता नहीं था कि अभियुक्त द्वारा बच्चों को जन्म दिया गया था।

44. इस न्यायालय ने इस मामले में प्रथमदृष्टया साक्ष्य का विधिक विश्लेषण करते समय **न्यायिक सावधानी** बरती है ताकि यह सामान्य धारणा पर आधारित न हो।पार्टियों के आचरण और परिस्थितियों की जांच की गई है ताकि मन की स्थिति और चुप रहने के आचरण के बारे में अनुमान लगाया जा सके और उसके बाद अचानक 12 साल के बाद उस घटना का खुलासा किया और दुनिया के सामने बच्चों के पितृत्व का भी खुलासा किया।इस मामले का निर्णय वस्तुनिष्ठ रूप से शिकायतकर्ता के अवलोकन योग्य आचरण पर केंद्रित है, जिसमें उसका तर्क भी शामिल है कि वह इन 12 वर्षों से कुछ तस्वीरों के बारे में भयभीत थी, जिसे उसने इन 12 वर्षों में नहीं देखा था और न ही पुलिस द्वारा उन्हें बरामद किया गया था।

45. अतः, इस मामले का निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित है कि उसकी असम्मति के संबंध में उसकी प्रस्तुति उसके आचरण के तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विश्वसनीय नहीं पाई गई थी। इस मामले में

शिकायतकर्ता का वास्तविक संचार व्यवहार **निर्विवाद मौन** रहा है, किसी को सूचित नहीं किया गया, हालांकि 12 वर्षों तक हर कदम पर चोट लगने के डर की कमी और शिकायतकर्ता द्वारा बिना किसी शिकायत के कुछ अंतराल पर अभियुक्त द्वारा बच्चों को जन्म देने के बारे में विशिष्ट साक्ष्य, किसी भी समय ली गई अनुचित फोटो या बनाई गई वीडियो की अनुपस्थिति में, यह आरोप के स्तर पर भी प्रथमदृष्टया सम्मति की अनुपस्थिति में विश्वास करने के लिए कोई **साक्ष्य आधार का मामला नहीं** है।

iii. सम्मति से सहवास बनाम यौन उत्पीड़न

46. वर्तमान मामलों के रूप में निष्कर्ष निकालने के लिए, सम्मति के महत्वपूर्ण मुद्दे, जो सम्मति से यौन संबंध या यौन उत्पीड़न के बीच विभाजन रेखा है, की जांच मामले के तथ्यों के आलोक में जांच की जानी थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के 12 साल के संबंध और किसी को भी कुछ शिकायत किए बिना कुछ समय इस यौन संबंध से पैदा होने वाले दो बच्चों की कहानी उनके यौन संबंध और व्यवहार के लंबे वर्षों से अनुमानित निहित और व्यावहारिक सहमति की ओर इशारा करती है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में निरेतर सम्मति की भावना पर आधारित है।

iv. 2 वर्षों की अकारण देरी

48. 12 वर्षों तक अभियोक्त्री की चुप्पी अस्पष्ट बनी हुई है।

49. यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि प्रत्येक मामले को उन विशिष्ट तथ्यों के आधार पर आंका जाना चाहिए जो इससे प्रकट होते हैं। वर्तमान मामले में, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोक्त्री एक वयस्क, परिपक्व विवाहित महिला थी जिसकी शादी को लगभग 2 साल हो गए थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह शादी से नाखुश थी। वह एक कामकाजी महिला थी और उसने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसे यह नहीं पता था कि अभियुक्त की शादी हुई थी या उसने उसे गलत तरीके से बताया था। इसलिए, वह इस तथ्य से अवगत थी कि दोनों की कानूनी रूप से अलग-अलग पार्टनर के साथ शादी हुई थी। उनके पास परिपक्वता और बुद्धिमत्ता भी थी, जो दोनों के कार्यों के महत्व और नैतिकता को समझने के लिए पर्याप्त थी, और वे इसके लिए सहमत थे। यह कहने के लिए कि इतने लंबे समय के रिश्ते के बाद, 12 वर्षों के बाद, उसने आरोपियों के प्रस्तावों का विरोध करने के लिए साहस जुटाया है, जब उसके पास पहले से ही दो बच्चे थे ,उसके दावे के विरूद्ध इशारा करते हैं। बल्कि यह भी इंगित करता है कि वह जानती थी कि दोनों एक ऐसे रिश्ते में थे जिसमें शामिल नैतिकता के कारण उसे गुप्त रखना था क्योंकि कानूनी रूप से विवाहित पति के साथ रहते हुए उसने अभियुक्त से दो बच्चों को जन्म दिया था।यह उसका मामला नहीं है कि वह यह नहीं जानती थी

कि वह अभियुक्त द्वारा उत्पन्न बच्चों को जन्म दे रही थी और न ही अपने पति द्वारा, हालांकि वह उन दोनों के साथ रह रही थी इसलिए, यह इंगित करता है कि वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह केवल अभियुक्त ही था जिसने उसके बच्चों को जन्म दिया था, न कि उसके पति ने। उन्होंने 12 साल तक चुप रहने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह के कृत्यों को जब तक संभव हो, गुप्त रखा जाना चाहिए।

50. अभियुक्त की ओर से भय की किसी भी घटना से मुक्त होने के बावजूद, केवल कुछ तस्वीरों और वीडियो पर जिन्हें दिन की रोशनी में नहीं देखा गया, उसने अभियुक्त के प्रस्तावों का विरोध नहीं किया था और वास्तव में न केवल उसके साथ अपने यौन संबंध को जारी रखा था बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न दो बच्चों को जन्म देने के लिए भी आगे बढ़ी थी। वह अपने निर्णयों और कार्यों के परिणामों के बारे में पूरी तरह से सचेत रही होगी और इसलिए, इस मामले में आरोप के चरण में भी कोई दो मत संभव नहीं हैं, लेकिन यह मानना कि उसने अपनी सम्मति से अभियुक्त के साथ यौन संबंध बनाने के लिए जानबूझकर सम्मति व्यक्त की थी और वह किसी भी तरह की चोट या तथ्य की गलत धारणा के कारण नहीं थी।

51. अभियोक्त्री के पति के कथन के परिशीलन से यह भी पता चलता है कि उसने उसमें यह स्वीकार किया कि इस बीच अभियुक्त इन सभी वर्षों अर्थात्

12-13 वर्षों से उनके घर पर भी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता रहा है।हालांकि, सितंबर, 2017 तक, यहां तक कि अभियोक्त्री को उनके रिश्ते के बारे में और इस तथ्य के बारे में पता नहीं था कि दो बच्चे अभियोक्त्री और अभियुक्त के यौन मिलन से पैदा हुए थे.

52. यह भी नोट किया गया है कि अभियुक्त की अपनी पत्नी से पांच बच्चे हैं। हालांकि यह तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला थी और इसलिए ऐसी महिला के प्रति समाज के दृष्टिकोण के कारण पुलिस में जाने में अनिच्छा थी। हालांकि, पुनरावृत्ति की कीमत पर वर्तमान मामले में अभियोक्त्री का आचरण यह है कि उसके 12 वर्षों के निरंतर संबंध की परिस्थितियों की समग्रता में, जहां उसने अभियुक्त के आधिकारिक आवास पर उसके साथ यौन संबंध बनाए रथे और उसके द्वारा दो बच्चों को जन्म दिया था, जबकि वह पहले से ही अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से पांच बच्चों का पिता था और यह तथ्य कि यह कि जो अभियुक्त था जो इस बहाने से कि वह अभियोक्त्री के भाई की तरह था अक्सर उनके वैवाहिक घर पर अभियोक्त्री से मिलने जाता रहा और अभियोक्त्री द्वारा उसके पति को किसी भी तरह की शिकायत नहीं की गई है और वह बिना किसी प्रतिरोध के बच्चों को जन्म देने के लिए आगे बढ़ी थी, बल्कि न्यायालय को यह ध्यान

देने के लिए बाध्य करती है कि मामले में इस तरह की अनिच्छा मौजूद नहीं थी।

<u>निष्कर्ष</u>

53. बलात्कार, यौन हिंसा और यौन उत्पीड़न कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के मामलों में, यौन सम्मति की परिभाषा की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण है ताकि ऐसी शिकायतों और मामलों में बलात्कार और सम्मति से यौन संबंध के बीच नाजुक संतुलन बनाया जा सके। सम्मति का मुद्दा, इस प्रकार, यौन उत्पीड़न के अपराध के विश्लेषण के लिए बारीकी से जांच की आवश्यकता है।

54. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्कार के मामलों में एक मामले से दूसरे मामले में तथ्यों पर निर्भर करते हुए सम्मति को केवल शिकायतकर्ता की निष्क्रियता या चुप्पी से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता या साबित नहीं किया जा सकता। तथापि, वर्तमान की भांति बिना किसी शिकायत की फुसफुसाहट के निरंतर सम्मति से न्यायालय को सम्मति विश्लेषण में सहायता मिलती है। अभियोक्त्री ने स्वीकार किया कि वह अपने स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार अभियुक्त के लगातार 12 वर्षों तक कहने पर उसके सरकारी आवास में जाती है। इसलिए, संबंध का यौन तत्व और उस यौन तत्व के लिए चल रही सम्मति की धारणा वर्तमान मामले में उसकी सचेत सम्मति के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान मामले में,

याचिकाकर्ता जानबूझकर अपनी सम्मति के परिणाम का मूल्यांकन करने में सक्षम थी और वह कार्य जो वह उसे यौन संबंध के लिए एक सचेत सम्मति भागीदार बनाने में शामिल थी.

55. यह विवादित नहीं है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त अपने-अपने जीवनसाथी से विवाहित हैं और विवाहित होने के बावजूद, अभियुक्त के साथ उनका संबंध 12 वर्षों तक बना रहा। पार्टियों के बीच संबंध दया बस्ती के रेलवे क्वार्टरों और पंचकुइयां रोड के रेलवे क्वार्टरों में हुए हैं, जो दिल्ली के सबसे व्यस्त और सबसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में से एक हैं, और क्वार्टरों का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि यह एक समान मार्ग है और एक दूसरे के करीब हैं। इसके अलावा, अभियुक्त लगातार अभियोक्त्री के घर पर भी जाता रहा और वह उसके आधिकारिक आवास पर उससे मिलती रही, जो यौन संबंध के लिए व्यक्त के साथ-साथ निहित सम्मति की ओर इशारा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता न ही किया। अभियोक्त्री ने 12 वर्षों तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और न ही उसने अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। अभियोक्त्री और अभियुक्त के रिश्ते से दो बच्चे पैदा हुए और उस अवधि के दौरान भी, उसने किसी भी अधिकारी के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। दिल्ली में एक घनी आबादी वाले स्थान पर उसकी इच्छा के खिलाफ पिछले 12 वर्षों के यौन संबंधों और अभियुक्त

के बच्चों को जन्म देने और 12 वर्षों तक उसकी निष्क्रियता की कहानी अस्पष्ट है। हालांकि, वह कहती है कि 12 वर्षों से उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था क्योंकि अभियुक्त ने अपने मोबाइल फोन में कुछ तस्वीरें ली थीं, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी कोई तस्वीर या मोबाइल फोन बरामद नहीं किया गया था।

56. यद्यपि, यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत रहता है कि आरोप के स्तर पर, एक लघु विचारण संचालित नहीं किया जा सकता है, तथापि, आरोप के बिंदु पर निर्णयों की कोई कमी नहीं है जो न्यायालयों पर यह कर्तव्य भी अधिरोपित करता है कि वे अभियोजन के डाकिया के रूप में कार्य न करें। और यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, तो घटना के 12 वर्षों के बाद लगाए गए आरोप चाहे बलात्कार हों या कोई अन्य अपराध और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में शिकायतकर्ता द्वारा अपनाई गई चुप्पी, न्यायालयों को अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मजबूत संदेह पैदा होता है या ध्यान दें।

57. वर्तमान मामले के तथ्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना के प्रयोजन के लिए भी अभियोक्त्री की कहानी के विरुद्ध गंभीर प्रश्न उठाते हैं।

58. बदलते सामाजिक संदर्भ और समकालीन समाज में, अभियुक्त के अधिकारों के विन्यास के बीच बाकी; अतिशेष; संतुलन बनाने के लिए इस

निर्णय को पारित करते समय कठोर सोच की आवश्यकता थी. उनके लंबे आपसी संबंध के कारण झूठे निहितार्थ के खिलाफ, जो 12 वर्षों तक जारी रहा और शिकायतकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतन्यायाधीश्ता निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं, लेकिन अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले की परिस्थितियों और तथ्यों में, यह एक न्यायाधीश के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। तथापि, ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य अभी भी यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त की समानता के मानकों को ध्यान में रखते हुए यौन हमले के स्थापित कानून के बीच बाकी; अतिशेष; संतुलन बना रहे।न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता को निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार और अभियुक्त के असद्भावीपूर्ण मुकदमे के पहले संरक्षित होने के अधिकारों का ध्यान रखा जाए।

59. इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यहां तक कि प्रथमदृष्टया, कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री ने तथ्य की किसी भी गलतफहमी या चोट के किसी भी डर के तहत अभियुक्त के साथ यौन संबंध बनाने के लिए अपनी सम्मति दी थी,

यहां तक कि यह भी कहा कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के लिए भा.दं.सं. की खंड 375 के अर्थ के भीतर एक प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

60. इस पृष्ठभूमि में और शिकायत में लगाए गए अभिकथनों को जैसे वे हैं, प्राथमिकी या आरोप-पत्र में भा.दं.सं. की आदेश 376/506 के तहत अपराध के आवश्यक या महत्वपूर्ण अवयवों को खोजना असंभव है। 475/2017 से संबंधित प्राथमिकी में कोई अनियमितता, अवैधता, अनौचित्य या दिशा नहीं है।

61. तथापि, यह **स्पष्ट किया** जाता है कि चूंकि यह न्यायालय विशिष्ट तथ्यों के आधार पर एक मामले पर विचार कर रहा है, जिसमें यह प्रश्न अंतर्वलित है कि क्या यौन क्रियाकलापों में संलग्न होने के लिए कोई स्वैच्छिक करार और सकारात्मक हां था या नहीं, यह न्यायालय अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में इस विशेष मामले के संदर्भ में कानूनों की प्रयोज्यता का परीक्षण कर रहा है, और प्रत्येक बलात्कार मामले के लिए सम्मति के संबंध में कोई कानून अधिकथित नहीं कर रहा है।

62. तदनुसार, वर्तमान याचिकाएं खारिज की जाती हैं। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसे भी खारिज कर दिया जाता है।

63. शिकायत किए गए आरोपों और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण को सीआरएल रेव. पी. 565/2019 में अभियोक्त्री के नाम को 'एक्स' के रूप में छिपाने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा, जैसा कि निर्देश दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुश्री एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य 2023 की आपराधिक अपील सं. 822-823 के मामले में पंजीकरण यह सुनिश्चित करना कि ऐसे मामलों में, यदि याचिका में अभियोक्त्री का नाम सामने आता है, तो मामले को अदालत के के पहले पेश किए जाने से पहले नाम हटाने के लिए पंजीकरण द्वारा संबंधित वकील को वापस कर दिया जाएगा।

64. निर्णय को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या.,स्वर्ण कांता शर्मा

मार्च 20, 2023/ज़ीपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*